दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 01 ▸ अंक : 03 ▸ गाजियाबाद, अप्रैल, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

इन मेडल्स से बदलेगी देश में टेबल टेनिस की तस्वीर... P-8

'प्रत्येक 13 यौन उत्पीड़न के केस में से एक केस दिल्ली में होता है'

उत्थान समिति की कार्यशाला में महिलाओं को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण

-उद्योग विहार, संवाददाता-

गाजियाबाद। वीमेन सेफ्टी कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाएं। इस अवसर पर उन्होंने देश में बढ रहे दुष्कर्म के मामलों के प्रति चिंता व्यक्त की और इन पर अंकुश लगाने की बात कही। उत्थान समिति, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स व स्लैब के संयुक्त तत्वावना में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि पूरे भारत में प्रत्येक 20 मिनट में रेप की वारदाता होती है और पुलिस केवल एक प्रतिशत मामलों में ही रिपोर्ट दर्ज करती है। जो बेहद गंभीर मामला है। प्रत्येक 13 यौन उत्पीड़न के केस में से एक केस दिल्ली में होता है। स्लैप की फाउंडर मृगान्का डडवाल ने कहा कि प्रत्येक घंटे में महिलाओं के साथ 26 वारदातें होती हैं। सन 2015 में 327394 केस महिलाओं के ऊपर अत्याचार के दर्ज किये गए थे। **शेष पृष्ठ तीन पर**

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम—जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2018

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8347.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/09/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	9311.12
Semi Skilled	8414.12
Un-Skilled	7634.12

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

निगम की सड़कों पर गुंडागर्दी की पार्किंग

साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के मोहन नगर में नगर निगम के पार्किंग के नाम पर पूर्व ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है अबैध पार्किंग शुल्क की उगाही आप को बता दे कि 31 मार्च को निगम द्वारा सभी पार्किंग का टेंडर निरस्त कर दिया गया था।

लेकिन पूर्व ठेकेदार द्वारा अभी भी मोहन नगर में पार्किंग के नाम पर पूर्व ठेकेदार के गुर्गे खुलेआम नियम के विरुद्ध अबैध वसूली कर रहे है।अगर इनका कोई विरोध करता है तो उसके गुर्गे अभद्रता और मारपीट तक उतारू हो जाते है। सरेआम हो रही वसूली को ना ही कोई रोकने वाला ना ही टोकने वाला है। सड़क निगम की है पर पार्किंग गुंडागर्दी की है। यह भी बताया जा रहा है पूर्व ठेकेदार भाजपा का कार्यकर्ता व साहिबाबाद विधानसभा के विधायक का बहुत करीबी है। उसी के बल पर करता है पार्किंग की अवैध वसूली। लेकिन ये कमाई गुंडागर्दी के हाथों में है। इनसे निगम या किसी सरकारी विभाग का कोई लेना देना नहीं है, ये अपने दम पर आपसे वसूली कर रहे हैं।

वाहन पार्किंग नगर निगम के लिए लाखों की आय का साधन है। उसके बाद भी वाहन पार्किंग को लेकर निगम अधिकारी गंभीर नहीं हैं।

हमारे संवाददाता ने जोनल प्रभारी शिव कुमार गौतम से अवैध निगम के नाम पर हो रहे पार्किंग की वसूली के बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो पूर्व ठेकेदार व गुर्गे के खिलाफ अबैध वसूली का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

वेतन न मिलने पर सुरक्षागार्डों का थाने पर प्रदर्शन

गाज़ियाबाद। इंदिरापुरम थाने में मंगलवार दोपहर एक कंपनी के सुरक्षागार्डों ने वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुरक्षागार्डों का आरोप है कि कंपनी पिछले चार महीने से उनका वेतन नहीं दे रही है। साथ ही कंपनी की तरफ से वेतन के रूम में मिला चेक भी बाउंस हो गया है। प्रदर्शन करने वाले सुरक्षागार्ड सुरेश चंद ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर-1 में उनकी कंपनी का कार्यालय है। कंपनी की तरफ से 47 सुरक्षागार्डों को ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में तैनाती की गई है। उनका आरोप है कि पिछले चार महीने से कंपनी की तरफ से सुरक्षागार्डों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वेतन मांगने पर कंपनी की तरफ से निकालने की धमकी दी जा रही है। उनका यह भी आरोप है कि दो महीना पहले कुछ लोगों को वेतन के रूप में चेक दिया गया था। जो बाउंस हो गया। मंगलवार दोपहर सभी सुरक्षागार्ड वसुंधरा सेक्टर-1 के कार्यालय में पहुंचे।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS &

PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- ❑ Payroll
- ❑ TDS
- ❑ ESI Act
- ❑ EPF Act
- ❑ Minimum Wages Act
- ❑ Bonus Act
- ❑ Payment of Gratuity Act
- ❑ Standing Order
- ❑ Workmen Health & Safety Policy
- ❑ First Aid Training & Certificates
- ❑ Factory Plan & Site Plan
- ❑ Factory Act-1948
- ❑ Shop & Establishment Act

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
दिल्ली–एनसीआर
गाजियाबाद, अप्रैल, 2018

अब सीधे बैंक में आएगी कर्मचारियों की सैलरी

-उद्योग विहार, संवाददाता-

गाजियाबाद। अब कर्मचारियों को नकदी सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि नियोक्ता को सीधे बैंक में सेलरी ट्रांसफर करनी होगी।

- कर्मचारियों को सिर्फ बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएस के माध्यम से ही मजदूरी/सैलरी देनी होगी

लेवर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में पैमेन्ट ऑफ वेजेस (मजदूरी भुगतान संशोधित अधिनियम) 2017 में सैक्शन-6 में बड़ा बदलाव किया गयाा है। जिसके तहत अब किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को सिर्फ बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएस के माध्यम से ही मजदूरी/सैलरी देनी होगी। सिर्फ आकास्मिक या अस्थायी कर्मचारियों के केस में 3 माह में केवल एक बार 5 हजार रुपए से अधिक नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है।

जबकि कर्मचारी नगद भुगतान के लिए एक प्रार्थना-पत्र स्वप्रमाणित आधार कार्ड की कापी के साथ देगा। ऐसा ना करने पर कड़े दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

किसी फेडरेशन की जागीर नहीं हैं खिलाड़ी: राज्यवर्धन सिंह राठौड़

नई दिल्ली। भारत में खिलाड़ी फेडरेशन या खेल संघों के मोहताज होते हैं. सरकार चाहकर भी इन खेल संघों पर नकेल नहीं कस पाती. लेकिन, खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दावा किया है कि अब ऐसा नहीं होगा. राठौर ने न्यूज18 से बातचीत में खेल संघों को तो चेताया लेकिन इनमें राजनेताओं का कब्जा खत्म करने से इनकार किया. उनका मानना है कि समस्या राजनेता या कोई वर्ग विशेष नहीं बल्कि व्यक्तिगत सोच है. राठौड़ ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ सरकार की कोशिशों का भी नतीजा है. खेल मंत्री ने बताया कि पिरामिड स्ट्रक्चर में खेलों की आधारभूत सुविधा मुहैया कराने और ओलंपिक खेलों के लिए महौल बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसमें खेल संघों की भी बड़ी भूमिका होगी, लेकिन उन्हें अपना रवैया बदलना होगा. उन्होंने कहा कि खेल संघों को खेल और खिलाड़ियों को अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए. राठौड़ ने कहा, इस विश्वास के साथ कि जो भी हमें करना है वो मिलजुलकर करना है. खेलों को जिन्होंने अपनी जागीर बना रखा है, उन्हें पारदर्शिता लानी होगी और नया सिस्टम अपनाना पड़ेगा क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा लगाकर खेलता है तब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है इसे मैं खिलाउंगा. देश का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी भारत के हर नागरिक के मान सम्मान का प्रतीक होता है. ऑस्ट्रेलिया में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को मिल रही सफलता पर खुशी जताते हुए राठौड़ ने कहा, हम इस बार कम खिलाड़ी भेजकर भी अधिक स्वर्ण ला रहे हैं. साथ ही उन खेलों में भी पदक जीत रहे हैं जिनमें हमारा प्रदर्शन पहले खराब रहता था.

तालमेल का अभाव एक बड़ी आबादी पर भारी

-उद्योग विहार, संवाददाता-

गाजियाबाद। केंद्र एवं प्रदेश में बीजेपी की सरकारों के सत्ता में आने के बाद भले ही तमाम सरकारी महकमों के बीच तालमेल स्थापित करने के दावे किए जा रहे है,लेकिन इस तालमेल के अभाव का खामियाजा लाइनपार की एक बडी आबादी एकाएक उत्पन्न हुई जलभराव की समस्या के कारण उठा रही है बल्कि क्षेत्र में महामारी की संभावना बढ गई है। अब नगर निगम हालात के लिए एनएएचआई को जिम्मेदार ठहराते हुए पल्ला झाड रहा है।

यू तो दावा किया जाता है कि किसी भी नए विकास के प्रोजेक्ट को आरंभ करने से पहले तमाम सरकारी महकमों के बीच तालमेल स्थापित किया जाएगा,ताकि विकास के प्रोजेक्ट में किसी भी स्तर से देरी ना हो। निजामुद्दीन से मेरठ के बीच एक्सप्रेक्स वे निर्माण का केंद्र सरकार का अहम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थीं,वैसे तो ये प्रोजेक्ट कभी का पूरा कर लिया जाना था,लेकिन लगातार अडचन के चलते ये प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं पा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर गाजियाबाद नगर निगम एवं एनएएचआई के बीच टकराव बढ गया है।

टकराव का कारण एनएएचआई के द्वारा रोड चैडी करने में बाधक एनएएच 24 से लगे नालों की निकासी को पूरी तरह से बंद किया जाना है। नाले की निकासी

- लाइन पार के एक बडे हिस्से में उत्पन्न हुआ महामारी का खतरा

बंद किए जाने के परिणाम स्वरूप लाइन पार की एक बडी आबादी बगैर बरसात के जलमग्न हो गई है बल्कि लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। वैसे ही गर्मी का मौसम है। माना जा रहा है कि यदि यही हालात रहे तो क्षेत्र में महामारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नगर निगम समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय उत्पन्न हुए हालात के लिए एचएएचआई को जिम्मेदार ठहरा रहा है,जबकि एनएएचआई के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिस नाले को बंद किया गया है वह एनएएचआई के स्वामित्व का हिस्सा है।

जानकार बताते है कि इन तमाम हालात के लिए वह महकमें के प्रमुख जिम्मेदार है जिनका दायित्व रोड चौडा करने के इस कार्य के आरंभ होने से पहले ही तमाम अडचनों को दूर करना था। लाइन पार क्षेत्र के उन तमाम पार्षदों में गुस्सा है जिनके वार्ड सीमा क्षेत्र के भाग तालाब में तब्दील हो गए है। माना जा रहा है कि शनिवारमें प्रस्तावित सदन की बैठक के दौरान निगम अधिकारियों की पार्षदों के द्वारा घेराबंदी की जा सकती है।

निगम के लाइट विभाग में डेपुटेशन पर तैनात अवर अभियंता की तैनाती पर बबाल

- नगर निगम के लाइट विभाग के तमाम प्रकाश निरीक्षकों ने अवर अभियंता की तैनाती को लेकर खडे किए सवाल
- कहा नगर निगम के लाइट विभाग में अवर अभियंता का पद ही नहीं
- नगर आयुक्त से अवर अभियंता को पुनः मूल पद पर भेजे जाने का किया आग्रह

-उद्योग विहार, संवाददाता-

गाजियाबाद। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के एक अवर अभियंता को मेरठ मंडल के अपर आयुक्त राम नारायण सिंह के द्वारा डेपुटेशन के आधार पर नगर निगम के लाइट विभाग में तैनाती किए जाने के साथ ही विवाद खडा हो गया है। अपर आयुक्त के आदेश के अनुसार सप्ताह में तीन दिन अवर अभियंता नगर निगम के लाइट विभाग में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। लाइट विभाग के तमाम प्रकाश निरीक्षकों ने अवर अभियंता की तैनाती को लेकर सवाल खडे करते हुए नगर आयुक्त से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। लाइट विभाग के तमाम प्रकाश निरीक्षकों के द्वारा नगर आयुक्त को दिए गए लेटर में कहा गया कि मेरठ मंडल के अपर आयुक्त श्री धामा के द्वारा अवर अभियंता की तैनाती के आदेश 1 सितंबर 2017 में जारी किए गए थे। जो कि आठ माह पुराने है। अवर अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा किन कारणों से गाजियाबाद नगर निगम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकें। अब एकाएक उपस्थिति दर्ज कराया जाना आपत्ति जनक है।लेटर के माध्यम से खुलासा किया गया कि गजेंद्र पाल शर्मा का प्रदेश शासन के द्वारा स्थानांतरण सितंबर 2017 में झांसी कर दिया गया था। इस कारण अपर आयुक्त के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। नियमानुसार 90 दिन तक किसी आदेश का पालन नहीं होने की दशा में स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस चलते उपरोक्त आदेश पर कार्रवाई किया जाना वैधानिक नहीं है। नगर निगम गाजियाबाद के प्रकाश विभाग में शासन के द्वारा प्रकाश निरीक्षक के केवल छह पद स्वीकृत है।

अवर अभियंता का कोई पद स्वीकृत नही है। इसी कारण प्रकाश विभाग में कभी अवर अभियंता की तैनाती नहीं हुई है। प्रकाश निरीक्षकों के द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। तकनीकी कार्यों की देखरेख के लिए अधिशासी अभियंता जल आनंद कुमार त्रिपाठी जो इलैक्ट्रीक्ल से वीई डिग्री प्राप्त है। अतिरिक्त रूप से अधिशासी अभियंता प्रकाश का कार्य भी देखा जा रहा है। इसलिए विकास प्राधिकरण कैडर के अवर अभियंता को कैडर से बाहर नगर निगम कैडर में तैनात किया जाना न्याय संगत नहीं है। वैसे भी शासन के आदेश पर नगर निगम गाजियाबाद में स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में तब्दील करने का कार्य प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अगले सात सालों तक इसी संस्था के द्वारा लाइटों का रखरखाव किया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए छह प्रकाश निरीक्षक तैनात है। फिर बिना किसी वेतन भत्ते दिए अवर अभियंता प्राधिकरण कैडर की तैनाती का कोई औचित्य नहीं है। लेटर के माध्यम से ये भी आग्रह किया गया कि गजेंद्र पाल शर्मा के चरित्र कार्यप्रणाली के संबंध में 2004 से 2010 तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विधुत विभाग में किए गए कार्यों की जानकारी भी की जाए। कि श्री शर्मा कितने समाजसेवी है। जो बिना किसी बिना वेतन भत्ते के गाजियाद नगर निगम में सेवा उपलब्ध कराने में सहर्ष तैयार है। गजेंद्र पाल शर्मा अपर अभियंता को उनके मूल पद पर भेजे जाने की मांग की गई।

करोडों रूपए खर्च के बाद भी सीडब्लूआर का लाभ नहीं

गाजियाबाद। कई करोड रूपए खर्च करने के बावजूद हिंडनपार के वैशाली सेक्टर नौ और उससे लगे क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया भूमिगत जलाशय सीडब्लूआर का इलाके के लोगों को सात साल बाद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वजह इस सीडब्लूआर को जीडीए के द्वारा अभी तक भी नगर निगम के हेंड ओवर नहीं किया गया है। हैरत का पहलू तो ये है कि नगर निगम के जलकल महकमें के द्वारा जीडीए को पत्र लिखे जाने के बावजूद जीडीए के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। अब गर्मी का मौसम आरंभ होने पर पेयजल की स्थिति बिगडने पर नगर निगम के जलकल विभाग के द्वारा मामले को मेरठ मंडलायुक्त के सामने उठाया है। यहां बता दे कि हाल में खुलासा हुआ था कि वैशाली सेक्टर नौ में बसपा के शासन के काल के दौरान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के द्वारा चार हजार लीटर क्षमता का सीडब्लूआर का निर्माण कार्य कराया गया था। निर्माण कार्य 2008 के दौरान पूरा कर लिया गया था,लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जीडीए इसे नगर निगम के जलकल विभाग को स्थानांतरित करना ही भूल गया। मामला खुलने के बाद नगर निगम के जलकल विभाग के द्वारा जीडीए के अधिकारियों से सीडब्लूआर नगर निगम के हेंड ओवर करने का आग्रह किया गया। इसके लिए बाकायदा कई पत्र जीडीए को भेजे गए। नगर निगम के जलकल विभाग के अधिकारियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि लेटर को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। नगर निगम के सामने समस्या ये है कि उसे नलकूप से सीधे क्षेत्र में पानी की सप्लाई करनी पड रही है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

प्रत्येक 13 यौन उत्पीड़न के केस में से एक केस....

जो भी महिलायें यौन उत्पीड़न की शिकार होती है उनमे से केवल 30 प्रतिशत ही अपनी समस्या किसी से बता पाती हैं और केवल 1 प्रतिशत ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं।

कार्याशाला गाविंदपुरम स्थित डीडीपीएस में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने की। इससे पहले स्कूल की उप प्रधानाचार्य सीमा राज ने स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम में स्लैप की फाउंडर मृगान्का डडवाल ने स्कूल की बच्चियों को आत्मरक्षा के उपाय बताये तथा कैसे मनचलों का सामना किया जाये इस पर टिप्स दिए।

इस अवसर पर सत्येन्द्र सिंह ने कहा की प्रत्येक स्कूल के साथ ही प्रत्येक कारखाने एवं प्रतिष्ठानों में आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाना अनिवार्य है जिसमे एक प्रतिनिधि मैनेजमेंट का दो प्रतिनिधि श्रमिक पक्ष के तथा एक प्रतिनिधि किसी एन जी ओ का होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधियों में कम से कम आधे महिला होने चाहिए। ताकि किसी की भी शिकायत का निवारण किया जा सके तथा दोषियों को सजा मिल सके। इसका उल्लंघन करने पर पचास हजार तक जुर्माना एवं तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। साथ ही नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम होते रहना चाहिए।

स्कूल की लड़कियों ने इस अवसर पर खुल कर सवाल जवाब किये तथा इस अवसर पर बबिता सिंह, रूबी, रश्मि ने भाग लिया।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

सम्पादकीय

संबद्धता की गुत्थी

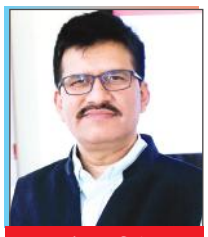

सत्येन्द्र सिंह

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को इस बात के लिए आड़े हाथों लिया है कि वह स्कूलों को संबद्धता देने के मामले में फुर्ती से काम नहीं कर रहा है। पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों को बोर्ड की संबद्धता देने के मामले में सीबीएसई जिस तरह से काम कर रहा है, वह चिंताजनक है। कैग ने इस बात पर खिन्नता जाहिर की कि लंबे समय तक स्कूलों के आवेदन बोर्ड के पास पड़े रहते हैं और उन पर फैसले नहीं किए जाते। कैग की इस तरह की टिप्पणियां बोर्ड के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े करती हैं। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि सीबीएसई सरकारी निकाय है जिसे बेहतर शिक्षा के लिए काम करना है।

स्कूलों को संबद्धता देने के जो नियम होते हैं, उनके मुताबिक बोर्ड को हर साल 30 जून या उससे पहले मिलने वाले स्कूलों के आवेदनों पर विचार कर छह महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन कैग ने पाया कि बोर्ड ने दो सौ तीन में से एक सौ चालीस स्कूलों को ही संबद्धता प्रदान की और इनमें मात्र उन्नीस स्कूल ऐसे थे जिनको छह महीने के भीतर संबद्धता मिली। बाकी एक सौ इक्कीस स्कूलों को संबद्धता देने और इस बारे में सूचित करने में सात महीने से तीन साल तक लग गए। कैग ने जो खुलासा किया है, वह चौंकाने वाला है। कई स्कूलों को तो बिना निरीक्षक समिति बनाए ही मान्यता दे दी गई। ऐसे में जो स्कूल बिना नियमों पर खरे उतरे जोड़-तोड़ कर मान्यता हासिल करते हैं, वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे पाएंगे? ऐसे स्कूल छात्रों की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का खयाल नहीं रखते और उनका एकमात्र मकसद पैसा कमाना होता है। ऐसे स्कूल बोर्ड के तय मानकों का पालन कैसे और क्यों करेंगे, यह सोचने वाली बात है।

सीबीएसई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाला संगठन है। स्कूलों को मान्यता देने से लेकर बोर्ड की परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने जैसी अहम जिम्मेदारी बोर्ड की ही है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। यानी जो भी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध होगा, उसे बोर्ड के तय मानकों का पूरा पालन करना होगा। ऐसे में अगर स्कूलों को बोर्ड से मान्यता नहीं मिलती है तो वे अपने हिसाब से स्कूल चलाते रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मार बच्चों के अभिभावकों पर पड़ती है। स्कूल मोटी फीस वसूलते हैं। वर्दी, किताबें, अन्य स्टेशनरी आदि अपने यहां से खरीदने को बाध्य करते हैं जो बाजार की तुलना में काफी महंगी बेची जाती हैं।

ज्यादातर स्कूलों के पास मानकों के अनुरूप न्यूनतम बुनियादी ढांचा भी नहीं होता। कैग ने अपनी जांच में कई स्कूलों में साफ-सफाई का घोर अभाव पाया। स्कूलों के नाम पर गली-गली में शिक्षा की दुकानें आसानी से देखी जा सकती हैं। हालांकि स्कूलों को मान्यता देने में देरी के पीछे बड़ी और व्यावहारिक वजह यह हो सकती है कि ज्यादातर स्कूल बोर्ड के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाते। स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन इस समस्या का समाधान तो बोर्ड को ही निकालना होगा।

संसद में चर्चा करने के लिए हंगामा करते रहे मगर चर्चा नहीं की

रोज के हंगामों और गतिरोधों के बीच संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। संसद के दोनों सदनों में देश ने जिस तरह माननीयों की उद्दंडता देखी उससे लगता है कि लोकमंच से लोकलाज का अंकुश हटता जा रहा है। साल 2018-19 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 24 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा व ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस पर बहस भी होनी चाहिए थी। जनता के मन में जो सवाल उठते हैं उनके उत्तर उन्हें मिलने चाहिए थे। इसी काम के लिए देश की जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है, लेकिन जनता के नुमाइंदों ने इतने बड़े बजट पर एक दिन से भी कम बहस की। बाकी का समय शोर-शराबे में यूं ही बर्बाद कर दिया।

29 जनवरी से 9 फरवरी और 5 मार्च से 6 अप्रैल तक दो चरणों में चले बजट सत्र में कुल मिलाकर करीब 2 सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। अब सत्तापक्ष और विपक्ष सड़कों पर उतर कर विभिन्न मुद्दों पर एकदूसरे को घेरने की बात कर रहे हैं परंतु जब यह काम तार्किक तरीके से सदन में किया जाना था तो न तो विपक्ष ने गंभीरता दिखाई और न ही सत्तापक्ष विरोध को नकेलने में सफल हो पाया। साल 2000 के बाद यह सबसे खराब संसद सत्र बताया जा रहा है। अबकी बार अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा तब देखी गई जब सांसद बार-बार सदन के वैल में आते दिखे और न केवल नारेबाजी के नाम पर हंगामा किया बल्कि गली-कूचे की राजनीति करते हुए तख्तियां लहराईं। कई बार तो इन तख्तियां से लोकसभा व राज्यसभा अध्यक्षों के चेहरे भी ढके जाते रहे। देखने में आ रहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण राजनीतिक दलों का ध्यान जनता के मुद्दों की बजाय अपनी राजनीति चमकाने की तरफ ज्यादा रहा। सत्र के दूसरे हिस्से की शुरूआत से ही टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वेल में आकर सांसदों का हंगामा रुटीन बन गया था।

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद भी कि जिन विशेष परिस्थितियों के चलते किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, वह आंध्र

प्रदेश पर लागू नहीं होतीं और सरकार उस राज्य के विशेष पैकेज देने को तैयार है इसके बावजूद हंगामा बरपा रहा। असल में आंध्र प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और टीडीपी व वाएसआर कांग्रेस का उद्देश्य परस्पर नीचा दिखा कर प्रदेश की राजनीति में अपनी सार्थकता साबित करना रहा न कि मुद्दे का हल निकालना। लगभग यही बात कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर लागू होती है, जब एआईएडीएमके के सांसदों ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। पार्टी ने राज्यसभा में कई बार स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

लेकिन सदन में हंगामे की वजह से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को राज्य में कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की बात कही थी। इसको लेकर तमिलनाडू की राजनीति में यह मुद्दा भड़क गया और खमियाजा भुगतना पड़ा संसद को। सत्र की शुरूआत से ही कांग्रेस, टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दल पीएनबी घोटाले पर वोटिंग वाले नियम 52 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं थी।

सरकार चर्चा के लिए राजी तो थी लेकिन नियम 193 के तहत, जिसमें सिर्फ बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं की जा सकती। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा होता रहा लेकिन बहस किसी भी नियम के तहत नहीं हो सकी। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर 12000 करोड़ रुपए के इस बैंक घोटाले का आरोप हैं। इसके अतिरिक्त सीबीएसई पेपर लीक मामले ने सदन को रोके रखा। अभी हाल ही में एससी/एसटी कानून में बदलाव के खिलाफ दलित संगठनों का देशव्यापी बंद बुलाया था। इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी गतिरोध रहा।

कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया वहीं सरकार ने भी संसद में साफ किया कि वह कानून को कमजोर नहीं बल्कि मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन गंभीर मुद्दों पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर पृष्ठभूमि तैयार करने का ही प्रयास किया।

देखा जाए तो विपक्ष ने बैंक घोटाले, पेपर लीक मामले व एससी एसटी एक्ट को लेकर हंगामा कर-के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। विपक्ष चाहता तो इन मुद्दों पर तर्कों व तथ्यों के सहारे सरकार की बखियां उधेड़ सकता था और यह तर्क सरकारी रिकार्ड में भी दर्ज होते। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने संसद का खूब लाभ उठाया और तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ बने जनमत में संसद के दौरान हुई बहसों का सबसे अधिक योगदान रहा।

तथ्य साक्षी हैं कि संसद के इन्हीं तर्कों को आधार बना कर ही आज देश के विभिन्न न्यायालयों में कांग्रेस व यूपीए सरकार के विभिन्न घटकों के नेताओं के खिलाफ अदालतों में केस विचाराधीन हैं। लेकिन कांग्रेस सदन का लाभ लेने से चूक गई। उक्त गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस सदन में केवल हंगामा करती रही और सरकार बाहर इनके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी ओर टीवी चचाओं में भाजपा नेता उक्त मुद्दों पर कांग्रेस को ही घेरते रहे और आज हालात यह हैं कि बैंक घोटालों व बैंकों के एनपीए के मामलों में सरकार से अधिक कांग्रेस दोषी नजर आने लगी है। फिलहाल जिस तरह संसद को क्षेत्रीय व गली कूचे की राजनीतिक का अड्डा बनाया जा रहा है वह देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को भी चाहिए कि वह अपने जनप्रतिनिधियों से इसका हिसाब जरूर लें कि उन्होंने विधानमंडलों में उनसे जुड़े कितने मुद्दे उठाए और कितनी समस्याओं का समाधान करवाया। ये लोकलाज ही है जो लोकमंच के साथ-साथ लोकतंत्र को पटरी पर बनाए रख सकती है।

कसौटी पर कानून

देश में जाति के आधार पर भेदभाव के बर्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के सामाजिक बर्ताव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए बाकायदा कानूनी व्यवस्था है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि इन कानूनों का सहारा लेकर कुछ निर्दोष लोगों को भी परेशान किया जाता है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के एक मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के दुरुपयोग की शिकायतों के मद्देनजर अब ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी होगी और आरोपी को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। मामला दर्ज करने से पहले उसके सही होने के आधार के बारे में डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। यही नहीं, अगर आरोपी सरकारी अफसर है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके उच्च अधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की रोकथाम के मकसद से ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल होता हो तो इस तरह की व्यवस्था वाजिब है। लेकिन सवाल है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग जिन सामाजिक मानदंडों और सोच के साथ जीते हैं, उसमें दमन-शोषण के शिकार समुदायों के लिए कानून के तहत इंसाफ का रास्ता क्या होगा! गौरतलब है कि पिछले साल महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का दावा किया था। इसके बरक्स करीब नौ महीने पहले महाराष्ट्र पुलिस ने विस्तृत आंकड़ों के आधार पर सरकार को सूचित किया था कि यह कानून दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पुलिस ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया था कि ज्यादातर आरोपियों के बरी होने का कारण गवाह का अपने बयान से पलट जाना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी मुकदमे में गवाह अपने बयान पर कायम नहीं रह पाता और आरोपी बरी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को कानून के दुरुपयोग का मामला कहा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हाशिये पर जीने वाले दलित-वंचित समुदायों की सामाजिक हैसियत क्या होती है और उनके सामने अपने दमन-उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के क्या विकल्प होते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए आज भी समाज की वर्चस्वशाली जातियों के लोग किन तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मंगलवार को ही सरकार ने लोकसभा में बताया कि अकेले 2016 में देश भर में दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपमान से जुड़े चालीस हजार सात सौ चौहत्तर मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, लगभग तीन महीने पहले जारी हुए राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2016 में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अपराध के मामलों में साढ़े पांच फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह किसी से छिपा नहीं है कि सामाजिक विकास और कमजोर तबकों के बीच सशक्तीकरण की प्रक्रिया धीमी या आधी-अधूरी होने की वजह से आज भी जातिगत अपराधों की कई शिकायतें सामने नहीं आ पातीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ती जागरूकता के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अब अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों और कानूनों का सहारा लेने के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस कानून के दुरुपयोग की रोकथाम करते हुए दलित-वंचित जातियों और समुदायों के लोगों को इंसाफ मिलने में कोई अड़चन नहीं पैदा की जाए।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2018

आरटीओ की पड़ताल 125 स्कूली बस मानक पर फेल

गाजियाबाद। संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से जनपद के सभी स्कूल की बसों की फिटनेस की आरम्भ की गयी पड़ताल के बाद से स्कूलों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा को लेकर सवाल उठ रहे है एक बात ये भी साफ होने लगी है की ज्यादातर स्कूल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे है। कमला नेहरु नगर ग्राउंड में रविवार को संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूली बसों की फिटनेस के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान जनपद की कुल 712 बस फिटनेस के लिए पहुंची। फिटनेस के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियम के अनुसार कुल 11 बिंदुओं पर जांच की गई। मानकों पर खरी न उतर पाने पर करीब 125 बसों के मालिक को नोटिस जारी किया गया है।

सूत्र बताते है कि बहुत से स्कूल दिल्ली सरकार के द्वारा प्रतिबंधित बसों की सेवाएं ले रहे इससे भी ज्यादा अहम तो मुफ्त परिवहन सुविधा के नाम पर एक बड़ी रकम की वसूली कर रहे है ज्यादातर स्कूलों के द्वारा महकमे में दिए गए सर्टिफिकेट की भी पड़ताल होती है तो इस बात का खुलासा होना तय है। यू तो स्कूलों में चलने वाली बसों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गाइंडलाइन जारी की हुई है। जिसकों लेकर विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाता रहता है।

जांच के दौरान कई बार विभागीय अफसरों के संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूली बस संचालकों की तरफ से मानक पूरे नहीं किए जा रहे है। मानक पूरा न होने पर बस ऑपरेटर बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करते है। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए शासन ने भी संभागीय परिवहन विभाग को स्कूल बसों के मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से सभी शैक्षणिक संस्थाओं में चलने वाली बसों की फिटनेस किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। कमला नेहरू नगर में स्थित मैदान में शिक्षण संस्थानों की बसे एकत्र हुई। जहां पर संभागीय परिवहन के अधिकारियों ने बसों की फिटनेस के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कुल 11 बिंदुओं की एक चेक लिस्ट बनाई और सभी बसों का पूरा निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभागीय कर्मचारियों ने बस के कागजात से लेकर सभी 11 बिंदुओं पर बसों की जांच की।

एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह और एआरटीओ आर.के. सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए कुल 11 बिंदुओं की एक चेक लिस्ट तैयार की गई है। मानकों के आधार पर जिन वाहन में खामी पाई गयी है। उस वाहन के स्वामी व चालक को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। 1 सप्ताह बाद दोबारा से संभागीय परिवहन कार्यालय में जाकर फिटनेस की एनओसी वाहन ऑपरेटर को लेनी होगी। 712 बसों में से 125 बसों के मानक पूरे नहीं मिले है।

इन बिंदुओं पर की गई विभाग द्वारा जांच

1. बस पर स्कूल बस लिखा है या नहीं।
2. बस की बॉडी पर स्कूल का नाम एवं फोन नंबर लिखा है या नहीं।
3. बस की खिड़की पर क्षैतिज ग्रिल या जाली लगी है या नहीं।
4. बच्चों के चढ़ने या उतरने के लिए दरवाजे पर फुट बोर्ड लगा है या नहीं।
5. सीट के पीछे या नीचे स्कूल बैग रखने की जगह है या नहीं।
6. बस में अग्निशमन लगा है या नहीं।
7. स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं।
8. बस में स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं।
9. इमरजेंसी गेट लगा है या नहीं।
10. प्रेशर हॉर्न लगा है या नहीं।

केवल सीएम के आने पर निकलता है फव्वारे से पानी?

गाजियाबाद। हापुड़ चुंगी चौराहे पर लगे फव्वारे के साथ अजीब घटना हो जाती है। आमतौर पर सुखा रहने वाले इस फव्वारे से केवल तभी पानी निकलता है जब गाजियाबाद में सीएम आते हैं। सच्चाई इन दोनो फोटो से परखी जा सकती है। पहली फोटो 30 मार्च की है जिस दिन सीएम गाजियाबाद आए थे। हापुड चुंगी चौराहे के फव्वारे से गिरती पानी की धार मन मोह रही है। दूसरी फोटो वर्तमान की है जिसमें आप देख सकते हैं कि फव्वारा सूख चुका है। यह फव्वारा इससे पहले भी तब ही चला था जब सीएम बनने के बाद योगी पहली बार गाजियाबाद आए थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि फव्वारे में पानी केवल सीएम के आने पर ही आता है।

छोटी सी आशा में मिला बड़ी उपलब्धियों को सम्मान

गाजियाबाद। समाज हित में किए गए हमारे छोटे से प्रयासों को जब सराहना और प्रोत्साहन मिलता है तो वह आगे चलकर एक बडी उपलब्धि बन जाते है। विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही

द्रोपदी एक आवाज कला मंच और नंदिनी फाउंडेशन ने किया महिलाओं को सम्मानित

ऐसी ही महिलाओं को द्रोपदी एक आवाज कला मंच और नंदिनी फाउंडेशन की ओर से छोटी सी आशा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

ये सम्मान उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें आज तक चैनल की एंकर शशि शर्मा, मिसेज यूनिवर्स एशिया माया सिंह औश्र एजीएस के डायरेक्टर अमित गर्ग द्वारा दिया गया। राजनगर स्थित आइएमए भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इस मौके पर शैली यशस्वी, अंशी मेहरा, द्रव्या माहेश्वरी ने सांस्कतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए कार्यक्रम में पूजा चडढा, पूनम शर्मा, नमिता भल्ला, गुरी जनमेजा, रोहिणी गोले, सुमिति, सुमेधा, सुनीता भाटिया, आशु मेहरा, पूजा करहाना, ममता गुप्ता, ममता सिंह, सुमन, शोभा अधिकारी, रचना साही, डा. प्रीति चौधरी, उमा अग्रवाल, नंदिनी श्रीवास्तव, रेशमा दयाल, अनुपमा वत्स को उनके समाज हित में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। मंच संचालन अमर आनंद व अदिति उन्मुक्त ने किया। इस मौके पर दमयंती, हरीश, मंजू सैनी, नवीन, भारती मौजूद थीं।

तमाम प्रयास के बाद पांच पार्किंग स्थलों का हुआ रास्ता साफ

गाजियाबाद। तमाम प्रयास के बाद 37 में से केवल पांच पार्किंग स्थलों का रास्ता साफ होने के बाद नगर निगम प्रशासन अवशेष पार्किंगों के नए सिरे से टेंडर निकालने की तैयारी में जुट गया है। वहीं निगम पार्षदों के द्वारा बगैर टैंडर प्रक्रिया के पार्किंग स्थलों पर मौजूदा में भी हो रही वसूली को लेकर सवाल उठाए जा रहे है बल्कि पार्किंग स्थलों पर निशुल्क पार्किंग का बोर्ड लगाए जाने की मांग उठने लगी है। यहां बता दे कि नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की कुल 37 पार्किंग स्थलों की टेंडर प्रक्रिया निकाली थीं। 27 मार्च तक प्रक्रिया के तहत आवेदन किए जाने थे।

निगम प्रशासन अब 32 पार्किंग स्थलों की नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा

तमाम रस्सा कशी के बीच शिवा टावर, एप्पल ट्री,आरटीओ और आर के टावर समेत कुल पांच पार्किंग स्थलों के रास्ते साफ हो पाए।

अब 32 पार्किंग स्थलों के नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया को फिर से अंतिम रूप दिया जाने लगा है। वहीं बीजेपी के निगम पार्षद मनोज गोयल निगम के मुख्य अभियंता एवं पार्किंग सेल के प्रभारी से मिले और इस बीच आरोप लगाते हुए कहा गया कि जिन पार्किंग स्थलों की टेंडर प्रक्रिया अभी तक इस बात की पडताल होनी चाहिए कि पूरी नहीं हुई है वहां पर किसके द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है और किसकी जेब में पार्किंग शुल्क का पैसा जा रहा है। इस दौरान पार्किंग सेल प्रभारी से अनुरोध किया गया कि जिन पार्किंग स्थलों की पार्किंग का रास्ता साफ नहीं हुआ है वहां पर मुफत पार्किंग का बोर्ड लगाया जाए।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2018

30 महीने पहले ही अपना पद छोड़ेंगी एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा, आरबीआई ने उठाए थे सवाल

नई दिल्ली। एक्सिस बैंक की प्रमुख शिखा शर्मा को अपने कार्यकाल पूरा होने के 30 महीने पहले ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। शर्मा वित्तीय क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला सीईओ हैं। उन्हें दिसंबर में कार्यकाल के ढाई साल पूरा होने से पहले 2018 को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह घोषणा तब हुई है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड के शिखा शर्मा को चौथी बार एमडी और सीईओ बनाने के प्रपोजल पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। यह प्रपोजल 8 दिसबंर, 2018 को दिया गया था जिसके अनुसार शिखा जुलाई 2018 से अपने चौथे कार्यकाल को शुरू करतीं।

हालांकि सभी को चौंकाते हुए एक्सिस बैंक ने सोमवार को घोषणा करते हुए बताया कि शिखा शर्मा जोकि साल 2009 से सबसे बड़े बैंक की बागडोर संभाल रही हैं उनका कार्यकाल 1 जून 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक ही होगा। उनके कार्यकाल को

छोटा करने के कारण को बताया नहीं गया है लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इसका लेना-देना आरबीआई द्वारा उन्हें चौथा कार्यकाल देने को लेकर उठाए गए सवालों से है। शिखा शर्मा का तीसरा कार्यकाल 31 मई 2018 को पूरा हो रहा है।

एक्सिस बैंक ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि बोर्ड ने शिखा शर्मा को सात महीने एक जून से 31 दिसंबर 2018 तक के छोटे कार्यकाल की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया है। इससे पहले पिछले साल 8 दिसंबर को बैंक ने कहा था कि बोर्ड ने शिखा को एक जून 2018 से 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त करने का फैसला किया है। हालांकि, शिखा शर्मा की पुनर्नियुक्ति पर आरबीआई की मंजूरी ली जानी बाकी थी।

आरबीआई ने आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक के सीईओ के बोनस को नहीं किया है अप्रूव

नई दिल्ली। प्राइवेट बैंकों के चीफ एग्जिक्युटिव ऑफिसर्स (सीईओ) को वित्त वर्ष के अंत में मिलने वाले बोनस को इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए बोनस के आकार पर सवाल उठाए हैं और बोनस प्रस्ताव पर अभी तक साइन नहीं किया है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि कि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के सीईओ को बोनस नहीं मिला है। जानकारों के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब बोनस मिलने में देरी हुई है। बैंकों में एक के बाद एक फ्रॉड उजागर होने की वजह से ऐसा हुआ है। आईसीआईसीआई बोर्ड ने सीईओ चंदा कोचर के लिए 2.2 करोड़ बोनस को मंजूरी दी है, जबकि एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को 1.35 करोड़ बोनस मिलेगा और एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी को करीब 2.9 करोड़ रुपये मिलना है।

होंडा के एक्टिवा को टक्कर देगी यामाहा की नई फसीनों, नए बदलाव के साथ फिर से हुई लॉन्च

नई दिल्ली। यामाहा मोटर्स इंडिया ने भारत में अपने नए 2018 यामाहा फसीनो स्कूटर को कुछ बदलावों के साथ लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की नई दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 54,593 रुपए है। इस नए स्कूटर में फसीनो एम्बलम और अपडेटेड क्राम गार्निश वगैरह अपडेट्स दिए गए हैं। नए फसीनो स्कूटर में विजुअल बदलाव किए गए हैं ताकि इसे बाजार के लिहाज से फ्रेश रखा जा सके। रेट्रो लुक से इंस्पायर्ड इस स्कूटर का डिजाइन यूनीक है। यामाहा ने इसमें कुछ नए ग्राफिक्स भी जोड़े हैं।

सात तरह के कलर ऑप्शन में होगा उपलब्ध

इसमें मॉडर्न ग्राफिक्स हैं और सीट कवर को अब ड्यूल कलर टोन से प्रीमियम फील दिया गया है। इससे यह अट्रैक्टिव लगता है। यह स्कूटर सात कलर चॉइसेज, ग्लैमरस गोल्ड,

डैपर ब्लू, बीमिंग ब्लू, डैजलिंग ग्रे, सिजलिंग क्यान, स्पॉटलाइट वाइट और सैजी क्यान के साथ अवेलेबल है।

इंजन में नहीं हुआ बदलाव

मैकेनिकली देखें तो फसीनो स्कूटर पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें सिंगल सिलिंडर वाला 113 सीसी इंजन दिया गया है। यह एयर कूल्ड इंजन 7,500 आरपीएम पर अधिकतम 7.1 पीएस का पावर और 5,000 आरपीएम पर 8.1 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन को यामाहा की ब्लू कोर तकनीक से लैस किया गया है। इससे इंजन एफिशिएंट बनता है और गर्मी की वजह से पावर लॉस भी कम होता है।

ट्यूबलेस टायर्स दिए गए

फीचर पुराने फसीनो मॉडल जैसे ही हैं। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और रियर मोनोशॉक दिया गया है। दोनों 10 इंच वील्ज हैं और इनमें ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। यामाहा इसमें केवल ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है। फसीनो का मुकाबला होंडा ऐक्टिवा 5जी, टीवीएस ज्यूपिटर आदि स्कूटर्स से बाजार में होना है।

13 अरब रुपये के शेयरों का नहीं कोई दावेदार

नई दिल्ली। करीब एक लाख से अधिक शेयरधारक ऐसे हैं जिनके पास देश की कुछ बड़ी कंपनियों के अरबों रुपये मूल्य के शेयर हैं लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एसऐंडपी बीएसई 100 फर्मों की शेयरधारिता रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जिसमें पाया गया कि इन कंपनियों के पास कम से कम 13.02 अरब रुपये मूल्य के शेयर ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। इन शेयरों का दावा नहीं करने के पीछे कई वजहें हैं, जिनमें वारिसों को अपने पूर्वजों की विरासत के बारे में पता नहीं है और शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। बिना दावे वाले शेयरों में सबसे ज्यादा मूल्य के शेयर आईटीसी के हैं। इसके पास 1.371 करोड़ शेयर ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है और इसका मूल्य करीब 3.6 अरब रुपये है। यह आंकड़ा दिसंबर तक हैं, जिसका विश्लेषण बिजनेस

स्टैंडर्ड ने किया है। इसी तरह रत्न एवं आभूषण कंपनी टाइटन के पास 1.6 अरब रुपये मूल्य के 17.1 लाख शेयर हैं, जिनके दावेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खनन कंपनी वेदांत के पास 95.7 करोड़ रुपये मूल्य के 34 लाख शेयर हैं। सलाहकार फर्म कॉर्पोरेट प्रोऊेशनल्स के पार्टनर अंकित सिंघी ने कहा कि हस्तांतरण प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के साथ लागू किया गया है। इससे पहले कंपनियों को सात साल तक बिना दावे वाले शेयरों के लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित करना होता था। नए प्रावधान के तहत अब शेयरों को भी हस्तांतरित करना होता है और संशोधित प्रावधान की अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी। सिंघी के मुताबिक अगर लाभांश लंबित हो और निवेशक सात की अवधि के दौरान कम से कम एक बार लाभांश का दावा किया हो तो हस्तांतरण से बचा जा सकता है। ऐसे कुछ हस्तांतरण किए भी गए हैं। जीह एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने अपने रिकॉर्ड में उल्लेख किया है, '31 दिसंबर, 2017 को खत्म हुई तिमाही के दौरान बगैर दावे वाले 2,124 शेयरधारकों के 111,070 शेयरों को आईईपीएफ खाते में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार हस्तांतरित किए गए हैं।' ऐसे शेयरों के हस्तांतरण में फजीर्वाड़े का पता चलने के बाद ही इस प्रावधान को अनिवार्य किया गया है। निवेशक शिकायत फोरम के हिनेश देसाई ने कहा कि हस्तांतरण में कोई समस्या नहीं है क्योंकि सरकार इसकी संरक्षक होती है और इन शेयरों की बिक्री नहीं हो सकती है। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि इन शेयरों को रिफंड के लिए आईईपीएफ के पास दावा किया जा सकता है।

टॉप 10 कारों में से शुरूआती पांच पर मारुति का कब्जा!

नई दिल्ली। देश के ऑटोमोबाइल मार्केट की दिग्गज कंपनियों मारुति सुजुकी और ह्यूंदै मोटर इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट के टॉप 10 स्लॉट में अपना दबदबा कायम रखा है। मारुति सुजुकी को कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट पर लगातार फोकस रखने का फायदा मिला है और उसने पहली बार बेस्ट-सेलिंग पैसेंजर कारों के सभी पांच टॉप स्लॉट पर कब्जा किया है। कंपनी की छोटी कार ऑल्टो ने सेल्स के लिहाज से अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। इसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,58,000 से अधिक यूनिटें बिकीं। इसके बाद मारुति के डिजायर, बलेनो, स्विफ्ट और वैगनआर मॉडल्स का नंबर रहा। लिस्ट में कंपनी के दो और मॉडल विटारा ब्रेजा और सेलेरियो ने भी जगह बनाई। ह्यूंदै ने ग्रैंड आई10, एलीट आई20 और क्रेटा के साथ बाकी की तीन पोजिशन हासिल की।

पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल्स गिरने से रेनॉ क्विड टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अधिक वॉल्यूम वाले स्मॉल कार सेगमेंट में कॉम्पिटीशन कम हो गया है।

जनरल मोटर्स का भारत से बिजनस समेटना, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का स्मॉल कार कैटेगरी से दूर रहना, टाटा नैनो, होंडा ब्रियो जैसे मॉडल्स का सफल न होना इसकी वजहें हैं। इसके चलते मारुति सुजुकी और ह्यूंदै ने कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर, राजीव सिंह ने बताया, 'देश में बिकने वाले पैसेंजर व्हीकल्स में से 68 पर्सेंट कॉम्पैक्ट कारें हैं। इसी वजह से इस सेगमेंट में मजबूत कंपनियों की वॉल्यूम अधिक है।' जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रॉफिट देने वाली सब्सिडियरी मारुति सुजुकी की कार बाजार में हिस्सेदारी 50 पर्सेंट हो गई है। इसका मतलब यह है कि देश में हर दो में से एक कार मारुति की बिकती है।

पिछले फाइनैंशल ईयर में मारुति सुजुकी की ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट की एवरेज ग्रोथ से अधिक रही। कंपनी का वॉल्यूम 14 पर्सेंट से अधिक बढ़कर 16.5 लाख पहुंच गया। इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, डोमेस्टिक मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स 7.8 पर्सेंट की वृद्धि के साथ 32.8 लाख यूनिट रही। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर लगभग 50.1 पर्सेंट के साथ अभी तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। ह्यूंदै मोटर इंडिया की पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिक्री 5,36,241 यूनिट और मार्केट शेयर 16.4 पर्सेंट रहा।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

नलकूपों का संचालन प्राइवेट कंपनी को दिए जाने से आपरेटर खफा

गाजियाबाद। नगर निगम के जलकल विभाग के द्वारा तमाम नलकूपों के संचालन का रखरखाव प्राइवेट कंपनी को दिए जाने के निर्णय को लेकर विवाद खडा हो गया है। जलकल कर्मचारी संघ ने निगम के तमाम आपरेटरों को सिटी जोन सीमा के नलकूपों पर तैनात किए जाने का आग्रह किया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि तमाम नलकूपों का संचालन प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है तो निगम के अपने आपरेटरों के सामने कार्य का संकट खडा हो जाएगा। ये भी सवाल किए गए कि इससे पूर्व जो नलकूपों का संचालन प्राइवेट कंपनियों को दिया गया उसके अनुभव की भी पडताल करायी जाए। यहां बता दे कि नगर निगम का जलकल विभाग एक बार फिर शहर भर के तमाम नलकूपों का संचालन लखनउ की प्राइवेट कंपनी को देने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब केवल कंपनी

- आपरेटरों ने उठाए सवाल कहा गए आटो माइजेशन के नाम पर लगवाएं गए उपकरण

के पक्ष में कार्य आदेश जारी किए जाने शेष है। कर्मचारी संघ का तर्क है कि नलकूपों का संचालन प्राइवेट कंपनी को दिया जाना नलकूपों को आटो माइजेशन के नाम पर करोडों रूपए खर्च के घपले पर पर्दा डाला जाना है। जिस वक्त नलकूपों का आटो माइजेशन कराया जा रहा था उस दौरान दावा किया गया था कि इस कदम के बाद नलकूपों पर आपरेटरों की आवश्यकता नहीं होगी। लाइट जाने पर खुद नलकूप बंद हो जाएंगे और इस बीच मोटर फूंकने का दूर तक भी खतरा नहीं होगी। नलकूपों का संचालन प्राइवेट कंपनी को दिए जाने से पहले सर्व प्रथम इस बात की शासन उच्च स्तरीय पडताल कराए कि वह तमाम उपकरण कहां गए जो एक बडी रकम खर्च करते हुए लगवाएं गए थे। आटो माइजेशन के नाम पर उपकरण लगवाने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही निगम के अपने अपरेटरों को सिटी जोन सीमा के नलकूपों पर तैनात किए जाने का भी आग्रह किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार के नाम पर सरकारी पैसे को ठिकाने लगाया जा रहा है। कौन सा नलकूप बंद है और कितने डोजर खराब पडे है ये देखने के लिए भी अफसरों पर वक्त नहीं है।

कांग्रेस के खिलाफ उपवास पर बैठे भाजपा सांसद, सियासत शुरू

नई दिल्ली। बिहार के भाजपा सांसद राजधानी सहित राज्य के विभिन्न संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत गुरुवार एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। भाजपा का आरोप है कि विगत दिनों कांग्रेस ने जिस तरह संसदीय लोकतंत्र को तार-तार कर संसद को ठप करने का घृणित प्रयास किया है, वह निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विधायकों और सांसदों से विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने के खिलाफ एक दिन का उपवास रखने की अपील की है। इस बीच उपवास को लेकर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। राजद नेता ने जहां इसे नौटंकी बताया, वहीं भाजपा नेता ने कहा कि यह छोला-भटूरा वाला नहीं, असली वाला उपवास है। पीएम मोदी की अपील पर बिहार में भी भाजपा सांसदों का एक दिवसीय अनशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अनशन कर रहे हैं तो नवादा में गिरिराज सिंह की अगुवाई में अनशन कार्यक्रम हो रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय में उजियारपुर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद -पटना में, राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा पटना में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मोतिहारी में, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर में, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव पालीगंज बाजार में, केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में, राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर नालंदा में, सांसद राजीव प्रताप रूडी छपरा में, सांसद हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आरा में उपवास पर बैठे हैं। रविशंकर ने कहा कि संसद चर्चा के लिये है लेकिन हाल में समाप्त हुए बजट सत्र के दूसरा भाग एक महीना बाधित हुआ जो कि दुर्भाग्य है। इस सत्र में सदन में कई बिल थे जिन पर चर्चा होनी थी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिये पीएम प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने ये प्रतिबद्धता बार-बार दिखाई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि दलितों के लिये क्या किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमने दलितों के उत्थान के लिये सरकार बनने से अभी तक कई नये स्किम दिये हैं। सबसे ज्यादा लोन दलितों को दिया है।

अपनी जनता और सीमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा प्रदर्शनी में कहा कि शांति के प्रति देश की सरकार की प्रतिबद्धता उतनी ही है जितनी की अपने लोगों तथा सीमाओं की रक्षा के लिए और इसके लिए सशस्त्र सेनाओं को हथियारों से लैस करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तमिलनाडु के तिरूवेदांती में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया में कई विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, शांति के लिए हमारी प्रतिबद्धता उतनी ही मजबूत है जितनी की हमारे लोगों और सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी ध्दृता। इसके लिए रणनीतिक रूप से स्वतंत्र रक्षा उद्योग परिसर की स्थापना करने सहित सशस्त्र सेनाओं को हथियारों से लैस करने के लिए हर कदम उठाने को हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मई 2014 तक कुल 118 निर्यात अनुमति दी गयी थी जिसकी कुल कीमत 57.7 करोड़ डॉलर थी। चार साल से भी कम समय में हमने निर्यात की

और 794 अनुमति दी है , जिसकी कुल कीमत 1.3 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा एक वक्त था जब रक्षा तैयारियों का महत्वपूर्ण मसला नीतिगत जड़ता के कारण प्रभावित होता था। हमने देखा है कि ऐसा आलस्य, अक्षमता और संभवत : कुछ छुपे हुए स्वार्थ किस प्रकार से देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन, अब नहीं, अब बिलकुल नहीं, कभी भी नहीं। प्रधानमंत्री ने रद्द किए गए एमएमआरसीए सौदे का अप्रत्यक्ष हवाला देते हुए कहा कि किसी ठोस परिणाम के बगैर हम 10 वर्ष चर्चा में नहीं लगाना चाहते हैं। वहीं कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के विरोध में द्रविड़ मुनेत्र कषगम(द्रमुक) के पुरोधा एम. करुणानिधि के घर एवं अरिवालयम में पार्टी दफ्तर और अन्य नेताओं के घरों की छतों काले झंडे फहराये गए हैं। सूत्रों के अनुसार विल्लुपुरम, विरुद्धुनगर, नगायी जिलों में विभिन्न विपक्षी दलों के कई कार्यकताओं के घरों की छतों पर काले झंडे फहराए गए। मोदी के तमिलनाडु के दौरे के दौरान द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन की ओर से काला झंडा फहराने फहराने की अपील पर कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया। स्टालिन ने आज सुबह काली कमीज पहनकर वैथीस्वरन कोइल से छह दिवसीय कावेरी राइटस रिट्रीवल रैली का शुभारंभ किया। इस रैली में भाग लेने वाले अधिकांश कार्यकर्ताओं ने काली कमीज पहन रखी थी। द्रमुक महिला मोर्चा नेता एवं सांसद कनिमोझी ने सैदापेट में पनागल पार्क के समीप अन्य महिला सदस्यों के साथ मोदी के दौरे के विरोध में काला झंडा आंदोलन शुरू किया।

एलिवेटेड रोड को नॉर्दर्न पेरिफेरल-वे से जोड़ा जाएगा

-उद्योग विहार संवाददाता-

गाजियाबाद। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन करहेड़ा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद जीडीए ने फेज-दो प्रोजेक्ट के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। सेकेंड फेज में एलिवेटेड रोड को नॉर्दर्न पेरिफेरल-वे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एलिवेटेड रोड के बाद करहेड़ा से नॉर्दर्न पेरिफेरल-वे तक नई 5किमी लंबी लिंक रोड बनाई जाएगी।

जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन से नूरनगर, सिकरोड होते हुए एनएच-58 में मोरटा मननधाम तक बनने वाले बाईपास का काम तेज कर दिया है। इस बाईपास के शुरू होने से राजनगर एक्सटेंशन की अंदरूनी सड़कों के साथ राजनगर एक्सटेंशन पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। वहीं, राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर और आगामी जुलाई से शुरू होने वाले हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट (रेपिड रेल) की वजह से मेरठ रोड पर जाम की

- इसके लिए बनेगा राजनगर एक्सटेंशन से चार किलोमीटर लंबा बाईपास
- बाईपास शुरू होने से यूपी गेट से मोरटा मननधाम तक केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा

समस्या बढ़ेगी। बाईपास शुरू होने से मेरठ रोड पर लगने वाले जाम से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकेगा।

लिंक रोड के लिए 4.50 किमी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और एलिवेटेड रोड के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल-वे तक बनने वाली पांच किमी लंबी लिंक रोड के लिए जीडीए पहले ही करीब 4.50 किमी जमीन किसानों से अधिगृहीत कर चुका है। अब केवल आधा किमी के क्षेत्र के अधिग्रहण की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। यह नई लिंक रोड एलिवेटेड रोड के बाद करहेड़ा, मोरटी, भोवापुर, शाहपुर से नॉर्दर्न पेरिफेरल-वे को जोड़ेगी। नॉर्दर्न पेरिफेरल बनने के बाद भविष्य में यहां से ईस्टर्न पेरिफेरल-वे के लिए एक कनेक्टिविटी रोड दी जा सकती है। इसके साथ ही राज नगर एक्सटेंशन दिल्ली और लोनी से जुड़ जाएगा

जीडीए ने मास्टर प्लान-2021 में नॉर्दर्न परिफेरल-वे का प्रावधान किया था। इसमें डासना से मेरठ रोड और मेरठ रोड से लोनी तक करीब 20 किमी लंबा नॉर्दर्न परिफेरल-वे बनाया जाना है। तीन साल पहले जीडीए बोर्ड बैठक में पहले मेरठ रोड से लोनी तक के बीच 12 किमी लंबी पेरिफेरल रोड बनाने का निर्णय हुआ था। इसमें छह गांवों में करीब 138 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जानी है। जीडीए ने मोरटा, मोरटी, शमशेरपुर, भनेड़ा, अटौर नंगला की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन ग्रामीणों के अधिक मुआवजे की मांग के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। नई लिंक रोड बनने से राजनगर एक्सटेंशन की सीधे लोनी व दिल्ली से कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस बाईपासशुरू होने से 20 मिनट में पहुंचेंगे यूपी गेट से मोरटा राजनगर एक्सटेंशन के अंदर और चौराहे पर जाम की समस्या के निदान के लिए प्राधिकरण की ओर से राजनगर एक्सटेंशन से चार किलोमीटर लंबा बाईपास नूरनगर, सिकरोड होते हुए मोरटा एनएच-58 तक बनाया जा रहा है। अभी बाईपास पर कुछ जमीनों पर किसानों से मसला सुलझा नहीं है। प्राधिकरण ने नूरनगर तक भूमि अधिग्रहण कर 45 मीटर चौड़ी सड़क बना दी है। इस बाईपास मार्ग पर केवल हल्के वाहन ही निकलेंगे। बाईपास शुरू होने से यूपी गेट से मोरटा मननधाम तक केवल 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा।

वायु प्रदूषण पर रोक को लेकर संसाधनों पर मांगी रिपोर्ट

-उद्योग विहार संवाददाता-

गाजियाबाद। बढते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कवायद तेज हो गई है। शासन के द्वारा संसाधानों पर तमाम विभागों से विस्तार पूर्वक रिपोर्ट मांगी है। इस कवायद के बीच शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी छिडकाव की भी योजना है। पानी छिडकाव के लिए किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता होगी इसके लिए शासन ने तमाम महकमों से जानकारी तलब की है। नगर निगम के जलकल महकमें का तर्क है कि उसे सबसे पहले दस ट्रेक्टर और उसके स्टाफ के साथ डीजल की आवश्यकता होगी। निगम के जलकल विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि महकमें पर 35 टेंकर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। हर वार्ड में दो दो टेंकर से छिडकाव के लिए कम से कम दस ट्रेक्टर की आवश्यकता होगी। एक ट्रेक्टर को प्रति घंटा 25 लीटर के हिसाब से रोजाना 250 लीटर डीजल और 15 हजार रूपए माह के हिसाब से चालक की आवश्यकता होगी।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

फिल्म–खेल–जगत

08 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2018

जाह्नवी कपूर गलती की सजा हाथ से निकल गया प्रोजेक्ट

श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में कोलकाता से अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर मुंबई वापस लौटी हैं। बॉलीवुड में एंट्री करते ही जाह्नवी के पास फिल्मों के और कई ऑफर्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी नासमझी की वजह से खो दिया। दरअसल, हुआ यूं कि फिल्म 'सिम्बा' को लेकर रोहित शेट्टी की पहली पसंद जाह्नवी कपूर थी। फिल्म को लेकर कई दिनों तक रणवीर सिंह के अपोजिट लीडिंग लेडी के नाम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। पहले खबर थी कि रणवीर सिंह के अपोजिट श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर को साइन किया जा रहा है, लेकिन बाद में सैफ की बेटी सारा को साइन कर लिया गया। जाह्नवी के हाथ से फिल्म निकलने का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबरों की मानें जाह्नवी के हाथ से रोहित शेट्टी और करण जौहर की फिल्म सिम्बा उन्हीं की गलती की वजह से निकल गई। सिम्बा की स्क्रिप्ट जाह्नवी और सारा दोनों को सुनाई गई थी, लेकिन रोहित की पहली पसंद जाहन्वी ही थी। फिल्म साइन करने से पहले ही जाह्नवी ने ये लीक कर दिया कि उन्हें फिल्म 'सिम्बा' ऑफर हुई है। इतना ही नहीं उन्होंने फिल्म साइन किए बिना ही ये भी कहना शुरू कर दिया कि वे रणवीर सिंह के साथ काम करने को लेकर काफी नर्वस हैं। ये तब की बात की जब फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर इसे मेकर्स ने ही फैसला नहीं लिया था। रोहित शेट्टी को जाह्नवी का अनप्रोफेशनल रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने जाह्नवी को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जाह्नवी की जगह प्रोजेक्ट में सारा की एंट्री हो गई। बता दें कि सारा के लिए भी ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले सारा केदारनाथ से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली थीं, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के चलते फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी गई। फिल्म 'सिम्बा' के जरिए पहली दफा रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी साथ में काम कर रहे हैं। ये तेलुगु फिल्म 'टेम्पर' की हिंदी रीमेक होगी।

टॉपलेस होकर इस एक्ट्रेस ने किया था प्रोटेस्ट, बैन के बावजूद नहीं मानी हार और अब करेंगी ये काम

कुछ दिनों पहले तेलुगू एक्ट्रेस श्री रेड्डी उस वक्त सुर्खियों में आई थीं जब काम न मिलने की वजह से प्रोटेस्ट किया था और इस प्रोटेस्ट के चलते वह टॉपलेस हो गई थीं। श्री रेडडी ने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के निमार्ताओं और निर्देशकों पर काम के बदले शोषण करने का आरोप लगाया था। उनके इस तरह प्रदर्शन के बाद हालांकि पुलिस ने श्री रेड्डी को हिरासत में ले लिया था यही नहीं मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें मेम्बरशिप नहीं देने का फैसला किया था। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से मेम्बरशिप नहीं मिलने पर अब श्री रेड्डी का बयान है। उन्होंने कहा कि वह इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि उन्हें फिल्म मेम्बरशिप नहीं मिली। अब यह पूरा मामला वकील पर छोड़ दिया है। वह अपने वकील ले आएं मैं अपने वकील के साथ अब कोर्ट में बात करूंगी। श्री रेड्डी ने आगे कहा कि 'प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार है और मैं वही बोलती हूं जो मेरा दिगाग कहता है।' इससे पहले श्री रेड्डी ने राणा डग्गुबती के भाई अभीराम डग्गुबती पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने अभीराम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभीराम ने उनके साथ हैदराबाद के एक सरकारी स्टूडियो में यौन शोषण किया था। सोशल मीडिया पर श्री रेड्डी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि सुरेश बाबू के छोटे बेटे ने मुझे धोखा दिया।

गणित के सवाल का गलत जवाब दे बैठीं सोनम कपूर, ट्विटर पर जमकर हुई धुलाई

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर फोटोशूट के कारण अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह बेहद अलग है। सोनम कपूर से माइक्रोब्लॉलिंग साइट पर एक गणित का सवाल पूछा गया जिसका सोनम कपूर ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जवाब दिया। सोनम का जवाब गलत होने के कारण सोशल मीडिया पर लोगों ने सोनम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल फिल्मफेयर मैगजीन के एडिटर जितेश पिलई ने एक गणित का सवाल करते हुए ट्विटर अकाउंट से एक फोटो साझा की। फोटो में ट्रायंगल की पजल थी जिसमें लिखा था बताइए कितने ट्रायंगल हैं? सोनम कपूर ने सवाल का जवाब देते हुए लिखा, सात। सोनम का गलत जवाब देखकर यूजर्स ने बेहद मजेदार कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, अगर आपको इससे भी ज्यादा दिख जाते तो आप राजघाट पर व्रत रख रही होती।

विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

नई दिल्ली। आईपीएल–11 में मंगलवार (17 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियन्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने 46 रन से जीत दर्ज की। ये मुंबई की इस सीजन में पहली सफलता थी। मैच में दोनों ही टीमों के कप्तानों ने शानदार बल्लेबाजी की।

एक ओर जहां रोहित शर्मा ने 94 रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने 62 गेंदों में 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 92 रन ठोके। भले ही विराट की टीम मुकाबले को हार गई, लेकिन खुद कोहली ने फैन्स का दिल जीत लिया और इसी के साथ वह आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था। आइए, जानते हैं कि इस फेहरिस्त में कौन–से बल्लेबाज टॉप–5 में शुमार हैं।

4619 रन विराट कोहली, 4558 रन सुरेश रैना, 4210 रन गौतम गंभीर, 4014 रन डेविड वॉर्नर

रोहित शर्मा और इविन लुईस (42 गेंदों पर 65 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी करके मुंबई इंडियन्स को पहली दो गेंदों पर मिले झटकों से उबारकर छह विकेट पर 213 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इनके अलावा क्रुणाल पांड्या ने 15, जबकि हार्दिक पांड्या ने नाबाद 17 रन की पारी खेली। मुंबई को पहली दो गेंदों पर झटके लग चुके थे। बावजूद इसके टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मिले इन मेडल्स से बदलेगी देश में टेबल टेनिस की तस्वीर...

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत की सफलता में इस बार टेबल टेनिस के सितारों ने चमक बिखेरी. भारत की मनिका बत्रा ने पहली बार महिला सिंगल्स का गोल्ड जीता. भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 8 पदक जीते. भारतीय टीटी खिलाड़ियों की यह सफलता काबिलेतारीफ मानी जा सकती है. भारत में टेबल टेनिस खिलाड़ियों का देश वापसी पर ऐसा स्वागत शायद ही पहले कभी हुआ हो. फैन्स ने देश वापसी पर चैंपियन खिलाड़ियों का ढोल–नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया. खिलाड़ियों ने भी फैन्स को ऑटोग्राफ देने और सेल्फी खिंचवाने के मामले में निराश नहीं किया. गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रांन्ज के साथ कुल 66 मेडल जीते. इसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 8 पदक भारत को टेबल टेनिस में मिले. गोल्ड कोस्ट में टेबल टेनिस टीम के लिए सबसे खास बात यह रही कि खिलाड़ियों ने महिला टीम इवेंट में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा. भारतीय टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3–1 से हराया और कॉमनवेल्थ इतिहास में गोल्ड जीतने वाली सिर्फ दूसरी टीम बनीं. 22 साल की मनिका बत्रा ने 2 स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता. इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में वे भारत की सबसे सफल खिलाड़ी साबित हुईं. मनिका के अलावा मौमा दास, अचंत शरत कमल, साथियान गणासेकरण, हरमीत देसाई और सानिल शेट्टी भी पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई. गौरतलब है कि लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा ने टेनिस और साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को देश को नई पहचान दिलाई है. कॉमनवेल्थ गेम्स में इन खिलाड़ियों को मिली इस कामयाबी से देश में टेबल टेनिस को भी एक नई दिशा मिलेगी.

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901/4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह